[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

I. Reports and Accounts (1980-81 and 1981-82) of the Shellac Export Promotion Council, Calcutta and related papers.

II. Textiles Committee (Amendment) Rules, 1983

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): Sir, I beg to lay on the Table:—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Twenty-fourth Annual Report and Accounts of the Shellac Export Promotion Council, Calcutta, for the year 1980-81 and the Audit Report on the Accounts together with Review by Government on the working of the Council.

(ii) Twenty-fifth Annual Report and Accounts of the Shellac Export Promotion Council, Calcutta, for the year 1981-82 and the Audit Report on the Accounts together with Review by Government on the working of the Council.

(iii) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) and (ii) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-7986/84 for (i) to (iii)]

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce (Department of Textiles) Notifications G.S.R. No. 850, dated the 2nd November, 1983, publishing the Textiles Committee (Amendment) Rules, 1983, under sub-section (3) of section 22 of the Textiles Committee Act, 1963. [Placed in Library. *See* No. LT-7947/84]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Asiatic Society Bill, 1984

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 19th March, 1984 agreed without any amendment to the Asiatic Society Bill, 1984, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 5th March, 1984.

REFERENCE TO THE BANNING OF THE ALL INDIA SIKH STUDENTS' FEDERATION.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मुझे एक निवेदन करना है। आज मैं एक व्यवस्था का प्रश्न और साथ ही साथ संसदीय नैतिकता का प्रश्न आप के समक्ष रखना चाहता हूं और उस पर आपसे रोशनी चाहता हूं। मैं किसी की नियत पर शक नहीं करता। आज एक खबर छपी है कि रात को बहुत देर कोई अधिसूचना के जरिए सिखों के उग्रवादी विद्यार्थी संगठन या उसके प्रदर्शन को बैन किया गया। जो उनकी हरकतें है उन से किसी को लेना-देना नहीं है, उन को हम कन्डेम करते हैं, मैं भर्त्सना भी करता हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब संसद बैठी हो तो क्या वह औचित्यपूर्ण नहीं था कि संसद को सूचना दी जा सकती या आज जो भी सम्बन्धित गृह मंत्री जी हों वह सदन को सूचित कर देते उस अधिसूचना के बारे में विनिश्चित इस के कि सूचना रात को जारी करके अखबार में छपने के बाद पता चला। यह नैतिकता का प्रश्न है। हो सकता है कि उन के अधिकारक्षेत्र में हो, जो कि नहीं होना चाहिए जब संसद बैठी हो, 'आर्डिनेंस नहीं' निकाल सकते तो एक्जीक्यूटिव आर्डर पर इस तरह अमलदरामद नहीं होना चाहिए।